



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 279]
No. 279]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 21, 2016/बैशाख 1, 1938

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 21, 2016/ VAISAKHA 1, 1938

रक्षोपाय महानिदेशालय

(केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2016

विषय: “अनरॉट एल्यूमिनियम (अलोय और गैर-अलोय एल्यूमिनियम)” के भारत में आयात से संबंधित रक्षोपाय जांच-प्रारंभिक निष्कर्ष - के संबंध में।

सा.का.नि. 435(अ).—सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 एवं सीमा शुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं उसका आकलन) नियमावली, 1997 के संबंध में;

(क) प्रक्रिया:

- सीमा शुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं उसका आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 5 के अंतर्गत मेरे समक्ष दिनांक 19/04/2016 को (i) मै. वेदांता लिमिटेड - एल्यूमिनियम एवं पावर, भुरकामुंडा, जिला झारसूगडा-768202, उड़ीसा (ii) मै. भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, एल्यूमिनियम सदन, कोर-6, स्कोप ऑफिस कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 एवं (iii) मै. हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, सेंचूरी भवन, तीसरी मंज़िल, डॉ. एनी बेसेंट रोड, वर्ली, मुंबई-400030 द्वारा अनरॉट एल्यूमिनियम (अलोय और गैर-अलोय एल्यूमिनियम) के वर्धित आयातों से घरेलू उत्पादकों को हुई गंभीर क्षति/खतरों से अनरॉट एल्यूमिनियम (अलोय और गैर-अलोय एल्यूमिनियम) के घरेलू उत्पादकों की रक्षा के लिए अनरॉट एल्यूमिनियम (अलोय और गैर-अलोय एल्यूमिनियम) के भारत में आयातों पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने के लिए अद्यतन आवेदन दिया गया है। उन्होंने इस अनरॉट एल्यूमिनियम (अलोय और गैर-अलोय एल्यूमिनियम) के वर्धित आयात के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को उनके निष्पादन में प्रपाती गिरावट के महेनजर अनंतिम रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण हेतु भी अनुरोध किया है।
- कथित रक्षोपाय नियमावली के नियम 5 के अधीन अपेक्षाओं को पूरा करने की दृष्टि से आवेदकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना को आवश्यक विचारणीय स्तर तक सत्यापित किया गया था। सत्यापन रिपोर्ट का गैर गोपनीय संस्करण सार्वजनिक फाइल में रखा गया है। यह संतुष्टि होने पर कि नियम 5 की अपेक्षाओं को पूरा किया गया था, भारत में अनरॉट एल्यूमिनियम (अलोय और गैर-

अलोय एल्यूमिनियम) के आयात के विरुद्ध रक्षोपाय जांच दिनांक 19 अप्रैल, 2016 के जांच शुरू करने के नोटिस के द्वारा शुरू की गई थी एवं उसी दिन इसे भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित किया गया था।

3. दिनांक 19 अप्रैल, 2016 के जांच शुरू करने के नोटिस की प्रति के साथ-साथ घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए आवेदन के गैर गोपनीय संस्करण को सीमा शुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं उसका आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 6(2) एवं 6(3) के अनुसरण में वाणिज्य मामले देख रहे मंत्रालय एवं अन्य संबंधित मंत्रालयों, मुख्य नियर्तिक देशों को भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से एवं घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए आवेदन में वर्णित किए गए अनुसार इच्छुक पक्षों को अग्रेषित किया गया था।
4. उपलब्ध जानकारी के अनुसार ज्ञात इच्छुक पक्षों को प्रश्नावली इस अनुरोध के साथ भेजी गई थी कि वे अपने विचारों से नोटिस जारी होने की तारीख से 30 दिनों के अंदर लिखित में अवगत करा दें।

(ख) महानिदेशक (रक्षोपाय) की प्रारंभिक राय एवं जांच परिणामः

5. मैंने घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए आवेदन का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है तथा रक्षोपाय महानिदेशालय के अधिकारियों ने एक्साइज रिकॉर्ड से इसकी सत्यापन रिपोर्ट बनाई है। मेरी टिप्पणियां, निष्कर्ष एवं संस्तुतियां आगे के पैराग्राफों में दी गई हैं।

(I) विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी):

6. सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 76 के सीमा शुल्क उपशीर्ष संख्या 7601 के अधीन विचाराधीन उत्पाद यथा अनराँट एल्यूमिनियम (अलोय और गैर-अलोय एल्यूमिनियम) को वर्गीकृत किया गया है। इसके अंतर्गत अध्याय शीर्ष 7601 के अधीन सभी उत्पाद श्रेणियाँ आती हैं।

(II) घरेलू उद्योग (डीआई):

7. सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 6(ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार वर्णित किया गया है:

“घरेलू उद्योग” का अर्थ है उत्पादक-

- i. समग्र रूप से समरूप वस्तु के अथवा भारत में प्रत्यक्षतः प्रतिस्पर्धी वस्तु के; अथवा
- ii. जिसका समरूप वस्तु का सामूहिक आउटपुट अथवा प्रत्यक्षतः प्रतिस्पर्धी वस्तु का आउटपुट भारत में कथित वस्तु के कुल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा होता हो।

8. (i) मै. वेदांता लिमिटेड – एल्यूमिनियम एवं पावर, (ii) मै. भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड एवं (iii) मै. हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से पीयूसी के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण हेतु आवेदन दिया गया है। आवेदन एवं आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए अद्यतन आंकड़ों के अवलोकन पर यह देखा गया है कि आवेदक भारत में पीयूसी के कुल उत्पादन के 50% से अधिक के लिए उत्तरदायी हैं अतः आवेदक घरेलू उद्योग के रूप में अर्हता रखते हैं।

(III) जांच की अवधि (पीओआई):

9. सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975, सीमा शुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं उसका आकलन) नियमावली, 1997, जीएटीटी के अनुच्छेद XIX एवं रक्षोपाय पर करार में यह स्पष्ट वर्णित नहीं किया गया है कि जांच की अवधि कितनी होनी चाहिए। रक्षोपाय उपायों पर विभिन्न केस कानूनों से यह स्पष्ट है कि न तो रक्षोपाय पर घरेलू कानून न ही रक्षोपाय पर करार एवं जीएटीटी के अनुच्छेद XIX जांच की अवधि पर विशिष्ट विशास-निर्देश उपलब्ध कराते हैं सिवाएँ इस तथ्य के कि वर्धित आयात एवं गंभीर क्षति पर निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए संगत जांच अवधि पर्याप्त रूप से लंबी होनी चाहिए। इस मामले में जांच की अवधि 2011-12 से 2015-16 तक ली गई है जो कि बाजार परिस्थितियों पर विचार करने के लिए एवं रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण, यदि कोई हो तो, की आवश्यकता को निर्धारित करने के लिए बहुत पर्याप्त है।

(IV) सूचना का स्रोतः

- (10) पीयूसी हेतु जनवरी, 2016 तक के आयात आंकड़े नियर्त आयात डाटा बैंक, वाणिज्य मंत्रालय, (<http://www.commerce.nic.in/eidb/icomq.asp>) से लिए गए हैं एवं 2011-12 से 2015-16 तक के घरेलू आंकड़े आवेदकों द्वारा दिए गए हैं एवं उनको विभाग द्वारा एक्साइज रिकॉर्ड्स के आधार पर एवं यूनिटों द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्ड के आधार पर आवश्यक समझे गए स्तर तक सत्यापित किया गया है।

(V) प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता:

(11) डीआई ने कुछ सूचना को गोपनीय आधार पर उल्बध कराया है एवं दी गई सूचना/आंकड़ों पर गोपनीयता रखने की मांग की है। रक्षोपाय नियमावली, 1997 के प्रावधानों के अनुसार एवं व्यापार-सूचना संख्या एसजी/टीएन/1/97, दिनांक 06.09.1997 के अनुसार रक्षोपाय हेतु आवेदन के अगोपनीय संस्करण को डीआई ने उपलब्ध कराया है। डीआई ने आवेदन प्रस्तुत करते समय गोपनीयता की मांग हेतु कारण प्रस्तुत किए हैं।

(12) रक्षोपाय नियमावली, 1997 एवं विश्व व्यापार संगठन (WTO) रक्षोपाय पर करार के अनुच्छेद 3.2 में भी गोपनीयता का प्रावधान है। आवेदक से ऐसी सूचना का खुलासा करना अपेक्षित नहीं है जो कि कंपनी की गोपनीय सूचना हो, जिसके खुलासे से कंपनी के व्यापार हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, पब्लिक डोमेन में न हो एवं जिसका आवेदक द्वारा पूर्व में कभी सार्वजनिक खुलासा न किया गया हो। मैंने आवेदन के गोपनीय के साथ-साथ अगोपनीय संस्करणों का अध्ययन किया है एवं जहां तक प्रारम्भिक जांच में आर्थिक मानदंड एवं डाटा का संबंध है, डी आई की गोपनीयता की मांग स्वीकार की जाती है।

(VI) अनपेक्षित गतिविधि :

13. जीएटीटी के अनुच्छेद XIX के साथ पठित रक्षोपाय पर करार राष्ट्रीय प्राधिकारियों को अनपेक्षित गतिविधियां जिनके कारण डीआई को गंभीर क्षति होती है, की जांच को वाध्य करता है कुछ अनपेक्षित गतिविधियां इस प्रकार हैं:-

(i) यह पाया गया है कि चीन, जो कि एल्यूमिनियम का एक मुख्य उत्पादक देश है और विश्व के कुल एल्यूमिनियम उत्पादन का लगभग आधे का उत्पादन करता है, की अर्थव्यवस्था में हालिया, औचक एवं अप्रत्याशित गिरावट दर्ज की गई है जिसके कारण एल्यूमिनियम की खपत में कभी आई है। इसके परिणामस्वरूप चीन में एल्यूमिनियम उत्पादन क्षमता का बृहद सरप्लस हो गया है। एल्यूमिनियम की अतिरिक्त आपूर्ति जिसकी अब से पहले चीन में ही खपत होती रही है, अब वैश्विक बाजार में बिक्री के लिए बहुलता से उपलब्ध है और जिसके कारण एल्यूमिनियम के मूल्यों में मंदी निम्न स्तर पर पहंच गई है। कई मामलों में चीनी एल्यूमिनियम प्रगालकों (स्मेल्टर्सी) को प्रांतीय सरकारों द्वारा विजली समिक्षी के माध्यम से अब मदद दी जा रही है, जो कि उन प्रगालक (स्मेल्टर्सी) को चलाए रखने के लिए हाल ही में दी गई है क्योंकि इन प्रगालक (स्मेल्टर्सी) में किसी के बंद हो जाने कारण नौकरियों में कभी आ जाएगी और प्रांतीय सरकारें इस स्थिति का सामना नहीं करना चाहती। इसलिए कमजोर मांग के कारण अव्यवहार्य होने पर भी, प्रगालक (स्मेल्टर्सी) चल रहे हैं और एल्यूमिनियम के पहले से अधिक आपूर्ति बाजार में आपूर्ति जारी रखे हैं। क्योंकि चीन में सिलिल्यों पर निर्यात कर लगता है और मूल्य वर्धित उत्पादों पर कर में छुट प्राप्त है, इसलिए चीन का निर्यात एल्यूमिनियम के मूल्य वर्धित उत्पादों पर हो रहा है। कुछ मूल्य वर्धित उत्पाद जो फर्जी सैमिज के रूप में जाने जाते हैं, निर्यात छुट प्राप्त करने एवं निर्यात कर से बचने के ब्याल से निर्यात किए जाते हैं। ये फर्जी सैमिज गंतव्य स्थल पर सिल्लियों के रूप में पुनः प्रगालन हेतु प्रयुक्त होते हैं। यह सभी घरेलू उद्योग के लिए अनपेक्षित है।

(ii) दूसरी ओर मध्य-पूर्व में बहुत ही कम उर्जा लागत के कारण पिछले कुछ समय में एल्यूमिनियम की क्षमता में पर्याप्त वृद्धि के कारण वहां पर सरप्लस क्षमता हो गई है। विश्व बाजार में के अत्यधिक चीनी निर्यात के कारण पहले से ही व्याप्त एल्यूमिनियम की बहुलता के कारण, मध्य-पूर्व उत्पादकों ने अपना ध्यान नजदीकी भारत के भाड़ा अनुकूल बाजार पर केंद्रीत किया है।

14. यह पाया गया है कि उक्त परिस्थितियां अनपेक्षित हैं जिनके कारण भारत में पीयूसी के आयात में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

(VII) वर्धित आयात:

15. भारत में पीयूसी का आयात इस प्रकार है :

वित्तीय वर्ष	कुल आयात (एमटी)	अनुक्रमणित आयात
2011-12	2,42,533	100
2012-13	3,08,279	127
2013-14	3,48,889	144
2014-15	3,43,428	142
2015-16 (अप्रैल-जनवरी, 2016)	3,60,308	
2015-16 (वार्षिक)	4,32,370	178

यह देखा गया है कि क्षति अवधि के दौरान पीयूसी के आयात में तेजी से वृद्धि हुई है। 2011-12 में आयात 242533 मीट्रिक टन से 2015-16 (वार्षिक) तक 432370 मीट्रिक टन तक बढ़ गया है जिसके कारण 78% की वृद्धि दर्ज की गई है। 2014-15 से 2015-16 के बीच वृद्धि बहुत तेज व पर्याप्त थी।

(VIII) गंभीर क्षति एवं गंभीर क्षति की आशंका:

16. गंभीर क्षति : आवेदकों ने यह दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद के वर्धित आयात के कारण विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति हुई है एवं गंभीर क्षति होने की आशंका है। उन्होंने अपने दावे को न्यायोचित करने के लिए उत्पादन, मांग, इंवेंटरी एवं उद्योग के अन्य आर्थिक मापदंडों को उपलब्ध कराया है। घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का निम्नानुसार विश्लेषण किया गया है:

(क) उत्पादन: जांच की अवधि के दौरान डीआई का घरेलू उत्पादन बढ़ा है जैसा की नीचे दर्शाया गया है:

वित्तीय वर्ष	उत्पादन (एमटी)	अनुक्रमणित उत्पादन
2011-12	8,87,286	100
2012-13	9,31,776	105
2013-14	10,51,100	118
2014-15	13,53,271	153
2015-16	15,63,639	176

(ख) कुल उत्पादन के संबंध में वर्धित आयात: भारत में पीयूसी कई देशों से आयात होता है जिनमें मुख्य यूएई, मलेशिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका, ओमान, कतर, बहरीन एवं थाइलैंड हैं। पीयूसी के आयात ने वास्तविक मर्दों में एवम कुल उत्पादन की तुलना में वर्धित प्रवृत्ति दर्शाई है। वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान पीयूसी का उत्पादन एवं आयात (वार्षिक) इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	कुल आयात (एमटी)	अखिल भारतीय उत्पादन (एमटी)	अखिल भारतीय उत्पादन के संबंध में आयात का %
2011-12	2,42,533	19,27,464	13
2012-13	3,08,279	20,73,367	15
2013-14	3,48,889	20,88,900	17
2014-15	3,43,428	25,49,372	13
2015-16	4,32,370 (वार्षिक)	28,18,978	15

आयात 2011-12 में 242533 से 2015-16 (वार्षिक) में 432370 मीट्रिक टन बढ़ा है जो कि 78% की वृद्धि दर्शाता है। यह देखा जा सकता है कि आयात ठीक पिछले वर्ष 2014-15 की तुलना में हालिया वर्ष 2015-16 में 26% तक बढ़ा है जोकि मेरी दृष्टि में आकस्मिक, तेज एवं महत्वपूर्ण है।

(ग) मार्केट शेयर एवं बिक्री के स्तरों में परिवर्तन: (एमटी 000'में)

वित्तीय वर्ष	आयात	डीआई की बिक्री	सीमित उपभोग	अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	कुल मांग	मार्केट शेयर का प्रतिशत			
	आयात	डीआई (सीमित उपभोग के अलावा)	डीआई (सीमित उपभोग सहित)	अन्य					
2011-12	243	637	444	945	2,268	11	28	48	42
2012-13	308	718	568	997	2,592	12	28	50	38
2013-14	349	671	619	940	2,579	14	26	50	36

2014-15	343	670	605	1,135	2,764	12	24	46	41
2015-16	432	894	538	1,064	2,928	15	31	49	36
*(वार्षिक)									

2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान पीयूसी की मांग बढ़ी है। आयात का मार्केट शेयर (वार्षिक) 2011-12 में 11% से 2015-16 में 15% तक बढ़ गया है। इसी अवधि के दौरान मांग में डीआई का शेयर बढ़कर 28% से 31% हुआ है। यद्यपि सीमित उपभोग के साथ देखे जाने पर डीआई का शेयर मात्र 1% बढ़ा है।

(प) क्षमता उपभोग: हालांकि पीयूसी की मांग में पर्याप्त वृद्धि हुई है तथापि बढ़े हुए आयात से घरेलू उत्पादकों की उत्पादन क्षमता में पर्याप्त निष्क्रियता आई है जैसा कि नीचे दी गई सारणी में देखा जा सकता है:-

वित्तीय वर्ष	संस्थापित क्षमता(एमटी में)	उत्पादन (एमटी में)	क्षमता उपभोग (% में)	कुल मांग
2011-12	23,25,096	8,87,286	38	22,68,453
2012-13	23,17,954	9,31,776	40	25,91,862
2013-14	25,57,393	10,51,100	41	25,78,900
2014-15	29,04,841	13,53,271	47	27,54,114
2015-16	32,58,465	15,63,639	48	29,27,819

(छ) लाभ/हानि: डीआई की लाभप्रदता में 2015-16 तेज गिरावट आई है एवं डीआई को हानि हुई है। इसे निम्न तालिकानुसार देखा जा सकता है:-

वित्तीय वर्ष	घरेलू लाभ/हानि (रूपये प्रति किंवा. में) (अनुक्रमणित)
2011-12	100
2012-13	11
2013-14	(4)
2014-15	154
2015-16 (दिसंबर 2015 तक)	(231)

(च) इंवेंटरी: निम्न तालिका जांच-अवधि के दौरान इंवेंटरी के स्तरों को दर्शाती है:-

वित्तीय वर्ष	इंवेंटरी (एमटी में) अनुक्रमणित
2011-12	100
2012-13	53
2013-14	46
2014-15	97
2015-16	49

(छ) उत्पादकता एवं रोजगार: वर्धित क्षमता के साथ-साथ रोजगार के स्तर में भी वृद्धि हुई है।

वित्तीय वर्ष	उत्पादन (एमटी में)	रोजगार (संख्या)	प्रति कर्मी उत्पादकता (एमटी)
2011-12	8,87,286	100	77
2012-13	9,31,776	95	85
2013-14	10,51,100	112	81
2014-15	13,53,271	111	105
2015-16	15,63,639	105	129

(ज) कीमतों में मंदी : निम्न तालिका से यह जाना जा सकता है कि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान आयातित माल की उत्तराई तक के मूल्य की तुलना में बिक्री की उच्च लागत के कारण बिक्री मूल्य कम थे जिसके कारण घरेलू उद्योगों पर दबाव पड़ा एवं उन्हें हानि हुई।

विवरण	यूनिट	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
बिक्री की लागत (अनुक्रमणित)	रुपए/किग्रा	100	109	110	117	118
विक्रय मूल्य	रुपए/किग्रा	100	104	104	119	99
आयातित माल को उतारने तक का मूल्य (अनुक्रमणित)	रुपए/किग्रा	100	102	106	115	104
लाभ/(हानि) (अनुक्रमणित)	रुपए/किग्रा	100	11	-4	154	-231
कम मूल्य पर बिक्री (अनुक्रमणित)	रुपए/किग्रा	100	40	66	96	-32

17. यद्यपि बहुत से मानदंड हैं जिन पर डीआई ने सकारात्मक रूझान प्रस्तुत किया है, तथापि सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्रभावी कारक डीआई की लाभप्रदता है जिसमें गिरी हुई कीमतों पर होने वाले वर्धित आयात के कारण हाल ही में गंभीर गिरावट आई है। उपर्युक्त की दृष्टि में यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के वित्तीय मानदंडों में गिरावट है जिसके कारण डीआई को हानि हो रही है जिसके कारण घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है तथा घरेलू उद्योग को आगे और होने वाली क्षति से बचाने की दृष्टि से रक्षोपाय शुल्क के रूप में तत्काल सुरक्षा आवश्यक है।

18. इसके अतिरिक्त वर्तमान जांच में भी गंभीर क्षति की आशंका है। पीयूसी का आयात वास्तविक मदों में पर्याप्त एवं उत्पादन की तुलना में बढ़ा है। आयात में पर्याप्त वृद्धि के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है एवं भविष्य में भी पीयूसी का आयात बढ़ेगा तथा घरेलू उद्योगों को गंभीर क्षति की आशंका रहेगी।

(IX) वर्धित आयात एवं गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति की आशंका के बीच कॉजल लिंक :

19. कोरिया पर पैनल (पैरा 7.89-7.90) – “कारणों” के निर्धारण के लिए डेयरी द्वारा उल्लिखित बुनियादी दृष्टिकोण:

“इसके कॉजल लिंक के निर्धारण हेतु निष्पादन में हमारी राय है कि राष्ट्रीय प्राधिकारियों को यह विश्लेषण एवं निर्धारण किए जाने कि आवश्यकता है कि क्या वर्धित आयात के कारण हो चुकी गंभीर क्षति को दिखाने हेतु राष्ट्रीय प्राधिकारियों ने विचार किया है। अपने कारण निर्धारण में राष्ट्रीय प्राधिकारियों को उद्देश्यों के संगत तथ्यों एवं गणना योग्य प्रकृति, जिसने उस उद्योग की स्थिति को प्रभावित किया, की गणना हेतु उपकृत है। इसके अलावा, यदि राष्ट्रीय प्राधिकारियों ने वर्धित आयात के अलावा तथ्यों, जिन्होंने घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई है, की पहचान की है तो वे सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे तथ्यों के कारण हुई क्षति को वर्धित आयात से हुई क्षति के रूप में विचार नहीं किया गया है। एक कॉजल लिंक को स्थापित करने हेतु कोरिया को दिखाना है कि इसके घरेलू उद्योग को क्षति वर्धित आयात के कारण हुई है। अन्य शब्दों में, कोरिया को दर्शाना है कि एसएमपीपी के आयात से मिलक पाउडर एवं कच्चा दूध उत्पादन करने वाले घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। इसके अलावा घरेलू उद्योग की स्थिति का विश्लेषण करते हुए कोरिया प्राधिकारियों के पास अन्य तथ्यों के कारण हुई क्षति के अलावा वर्धित आयात पर ध्यान नहीं देना है।”

20. उपर्युक्त वर्णित मानदंडों कि गहन गणना दर्शाती है कि वर्धित आयात से गंभीर क्षति हुई है और गंभीर क्षति कि आशंका हो रही है। खतरा निर्धारण के प्रयोजन हेतु उद्योग कि स्थिति को प्रभावित करने वाले उद्देश्यों के सभी संगत तथ्यों एवं गणना योग्य प्रकृति कि गणना की गई है। इस मामले में इस संबंध में निम्नलिखित संगत है:-

- विचारधीन उत्पाद का आयात वास्तविक मदों में जांच कि अवधि के दौरान 100% से 178% तक पर्याप्त रूप से बढ़ा है।
- आयात में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग का बाज़ार हिस्सा (सीमित उपभोग शामिल हैं) यथावत रहा जिससे घरेलू मांग में वृद्धि के बावजूद कम क्षमता उपभोग हुआ।
- उत्पाद को आयात की तुलना/प्रतिस्पर्धा में मुख्यतः बिक्री किया जाता है।
- 2015-16 की वर्तमान अवधि में आयातित माल के उतारने तक का मूल्य बिक्री की लागत की तुलना में कम है।

(v) घरेलू उद्योग को इंवेंटरी को कम करने एवं उत्पादन को बरकरार रखने हेतु घरेलू मूल्य के मुकाबले कम मूल्य पर निर्यात हेतु बाध्य होना पड़ा।

(vi) घरेलू उद्योग की लाभप्रदता कम हो गई है एवं उन्हें 2015-16 के दौरान पर्याप्त धारा हुआ है।

21. उपरोक्त की दृष्टि में मैं पाता हूँ कि वर्धित आयात एवं घरेलू उद्योग को हुई क्षति में सीधा संबंध है क्योंकि आधार वर्ष 2011-12 की तुलना में 2015-16(वार्षिक) में आयात 78% तक बढ़ गया है इसने घरेलू उद्योग के सम्पूर्ण निष्पादन को प्रभावित किया है जिसके कारण वर्ष 2015-16 में बहुत नुकसान हुआ है। इसलिए यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योगों को हुई क्षति बढ़े हुये आयात से हुई है।

(x) विकासशील देश:

22. विकासशील देशों से आयात के प्रतिशत को भी वर्ष 2015-16 हेतु परीक्षण किया गया है। मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका एवं थाइलैंड के अलावा अन्य विकासशील देशों का अकेले एवं समग्र रूप से भारत में कुल आयात क्रमशः 3% एवं 9% से कम है, इसलिए अधिसूचना संख्या 19/2016-सीमा शुल्क, दिनांक 05.02.2016 के अनुसार विकासशील देशों मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका एवं थाइलैंड के अलावा, से होने वाले विचाराधीन उत्पाद के आयात पर सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8(1) के प्रावधानों के अनुसार रक्षोपाय शुल्क आकृष्ट नहीं होगा।

(XI) विषम परिस्थितियां:

23. सीमा शुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं निर्धारण) नियमावली, 1997 के नियम 2(ख) के अनुसार “विषम परिस्थितियों” का अर्थ है परिस्थिति जिसमें यह स्पष्ट साक्ष्य है कि आयात ऐसी वर्धित मात्रा में एवं ऐसी परिस्थितियों में हो चुका है जिससे गंभीर क्षति हुई है अथवा गंभीर क्षति होने की आशंका हो गई है एवं अनंतिम रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपन में देरी से घरेलू उद्योग को अपूर्णीय नुकसान होगा।

24. दिनांक 29.07.1997 की अधिसूचना सं 35/97 – एन टी – सीमा शुल्क के द्वारा अधिसूचित सीमा प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं उसका आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 9 विहित करता है कि महानिदेशक जांच कि कार्रवाई में तेजी से आगे बढ़ेगे तथा महत्वपूर्ण परिस्थितियों में “गंभीर” अथवा “गंभीर क्षति की आशंका” के संबंध में वे प्रारम्भिक निष्कर्ष भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। जांच को शासित करने वाले सिद्धांत सीमा शुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं उसका आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 6 में दिये गए हैं। कथित नियमावली के नियम 6 व 9 का समरस पठन इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अनंतिम रक्षोपाय शुल्क कि त्वरित संस्तुति के लिए प्रदत नियम प्रारम्भिक जाँचों पर आधारित हैं। कथित नियमावली का नियम 15 ऐसे मामले में जहाँ जांच के निष्कर्ष के पश्चात अधिरोपित रक्षोपाय शुल्क पहले से ही अधिरोपित तथा संग्रहीत अनंतिम शुल्क से कम है, के रक्षोपाय शुल्क के अंतर कि वापसी किए जाने के प्रावधान के संबंध में है।

25. भारत में पीयूसी के आयात में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। आधार वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2015-2016 में आयात में 78% एवं 2014-15 और 2015-16 के मध्य 26% की वृद्धि हुई है। कम कीमतों पर आयात की इस वृद्धि के कारण घरेलू बाज़ार में कीमतों में गिरावट आई है। जिसके कारण डीआई को विक्री लागत से कम कीमतों पर बेचने के लिए बाध्य होना पड़ा। इसलिए जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की विशाल क्षमताओं को अप्रयोज्य तथा बेकार बना दिया। यद्यपि, घरेलू उद्योग की विशाल स्थापित क्षमता है तब भी पीयूसी की घरेलू मांग में वृद्धि के बावजूद अपने उत्पादन को बढ़ाने में अक्षम रहे हैं।

26. घरेलू उद्योग के लाभ प्राप्त करने की क्षमता में समय के साथ तेज गिरावट से ऐसी स्थिति आ गयी है कि घरेलू उद्योग को गंभीर वित्तीय घाटे उठाने पड़ रहे हैं तथा वे अपने भविष्य कि क्षमता को अपूरणीय क्षति पहुँचाए बिना लंबे समय तक टिकने में कामयाब नहीं हो सकते।

27. मैं पाता हूँ कि यही वे कारक हैं जिनके कारण इस मामले में विषम परिस्थिति बनी जिन्होंने घरेलू उद्योग के सम्पूर्ण निष्पादन को प्रभावित किया है एवं घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति पहुँचाई है अथवा गंभीर क्षति की आशंका उत्पन्न कर दी है। इसलिए यह उचित माना गया है कि घरेलू उद्योग को और क्षति से बचाने के लिए आयात में वृद्धि को रोकना होगा।

(XII) निष्कर्ष तथा संस्तुति:

28. उपर्युक्त प्रारम्भिक निष्कर्षों के आधार पर मैंने यह देखा कि पीयूसी के आयात में वृद्धि ने घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति पहुँचाई है तथा इससे इन्हें गंभीर क्षति की आशंका है। इसके कारण हाल कि अवधि 2015-16 में घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटा उठाना पड़ा है। वित्तीय घाटों के कारण डीआई ऐसी परिस्थितियों कि ओर अग्रसर हो सकते हैं जहाँ वे वित्तीय देनदारी के नीचे आ सकते हैं व भविष्य में अव्यवहार्य हो सकते हैं। अतः मैंने पाया कि जहाँ रक्षोपाय उपाय लागू करने में देरी घरेलू उद्योग को अपूरणीय क्षति पहुँचा सकती है वहाँ गंभीर

परिस्थितियाँ पाई जाएंगी। अतः गंभीर क्षति तथा गंभीर क्षति की आशंका के अंतिम निर्धारण को लंबित करते हुए 200 दिनों की अवधि के अनंतिम रक्षोपाय शुल्क को तत्काल अधिरोपित किए जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। घरेलू उत्पादकों (गोपनीय) द्वारा पीयूसी की विक्री लागत, बिना ब्याज के विक्री लागत पर उचित प्रतिलाभ, आयात शुल्कों का वर्तमान स्तर तथा पीयूसी के वर्तमान औसत आयात मूल्यों पर विचार करते हुये घरेलू उद्योग के हितों की रक्षा के लिए 200 दिनों के लिए यथा मूल्य 5% (पाँच प्रतिशत) की दर से, जिसे न्यूनतम माना गया है, में से एंटी इम्पिंग शुल्क को घटाते हुये, पीयूसी के आयात पर अनंतिम रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित किए जाने की संस्तुति की जाती है।

(XIII) आगे की प्रक्रिया :

29. विभिन्न पक्षों द्वारा प्रदान की गई सूचना का जहां आवश्यक होगा सत्यापन भी किया जा सकता है इसके लिए उन्हें अलग से सूचित किया जाएगा।

30. अंतिम निर्धारण किए जाने से पूर्व उचित समय पर जन सुनवाई आयोजित की जाएगी, इसकी तिथि के संबंध में अलग से सूचित किया जाएगा।

[फा सं डी-22011/10/2016/पार्ट-II]

विनय छावड़ा, महा निदेशक

DIRECTORATE GENERAL OF SAFEGUARDS

(Customs and Central Excise)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st April, 2016

Subject: Safeguard Investigation concerning Imports of “Unwrought Aluminium (Aluminium not alloyed and Aluminium alloys)” into India- Preliminary Findings-Reg

G.S.R. 435(E).—having regard to the Customs Tariff Act, 1975 and the Custom Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 thereof;

(A) Procedure:

1. An updated application has been filed before me on 19/04/2016 under Rule 5 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997, by (i) M/s. Vedanta Limited –Aluminium & Power, Bhurkamunda, Distt. Jharsuguda-738202, Odisha (ii) M/s Bharat Aluminium Company Ltd, Aluminium Sadan, Core -6, Scope Office Complex, Lodi Road, New Delhi-110003 and (iii) M/s Hindalco Industries Limited, Century Bhavan, 3rd Floor, Dr Annie Besant Road, Worli, Mumbai 400030 for imposition of Safeguard Duty on imports of “Unwrought Aluminium (Aluminium not alloyed and Aluminium alloys)” into India to protect the domestic producers of “Unwrought Aluminium (Aluminium not alloyed and Aluminium alloys)” against serious injury /threat of serious injury caused by the increased imports of “Unwrought Aluminium (Aluminium not alloyed and Aluminium alloys)”. The domestic industry has also requested for imposition of provisional safeguard duty in view of steep deterioration in performance of the domestic industry as a result of increased imports of “Unwrought Aluminium (Aluminium not alloyed and Aluminium alloys)”.
2. In order to satisfy the requirements under Rule 5 of the said Safeguard Rules, the information presented by the applicant was verified to the extent considered necessary. The non-confidential version of verification report is kept in the public file. Having been satisfied that the requirements of Rule 5 were met with, safeguard investigation against imports of “Unwrought Aluminium (Aluminium not alloyed and Aluminium alloys)” into India was initiated vide Notice of Initiation dated 19th April, 2016 and published in the Gazette of India, Extraordinary on the same day.
3. A copy of the Notice of Initiation dated 19th April, 2016 along with copy of non-confidential version of the application filed by the domestic industry were forwarded to the Central Government in the Ministry dealing with Commerce and other Ministries concerned, Governments of major exporting countries through their embassies in India, and other interested parties as mentioned in the application filed by domestic industry, in accordance with Rule 6(2) and 6(3) of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997.
4. Questionnaires were sent to the known interested parties as per the information available with a request to make their views known in writing within 30 days of the initiation notice.

(B) Preliminary Observation and Findings of the Director General (Safeguards):

5. I have carefully gone through the application filed by the domestic industry and report of verification conducted by the officers of the Directorate General of Safeguards from the excise records. My observations, findings and recommendations are discussed in the succeeding paras.

(I) The product under Consideration (PUC):

6. The product under consideration is “Unwrought Aluminium (Aluminium not alloyed and Aluminium alloys)” classified under Customs heading No.7601 of Chapter 76 of the Customs Tariff Act,1975. It covers the entire product range under chapter heading 7601.

(II) Domestic Industry(DI):

7. Section 6(b) of the Customs Tariff Act 1975 defines domestic industry as follows:

“Domestic industry” means producers -

- i. as a whole of the like article or a directly competitive article in India; or
- ii. whose collective output of the like article or a directly competitive article in India constitutes a major share of the total production of the said article in India.

8. The application has been jointly filed by (i) M/s. Vedanta Limited –Aluminium & Power, (ii) M/s Bharat Aluminium Company Ltd and (iii) M/s Hindalco Industries Limited for imposition of Safeguard Duty on imports of PUC. On perusal of the application and latest data provided by the applicants it is seen that the applicants account for more than 50% of the total production of PUC in India and hence, the applicants qualify as Domestic industry (DI).

(III) Period of Investigation (POI):

9. The Customs Tariff Act, 1975, the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard duty) Rules, 1997, the Agreement on Safeguards and the Article XIX of GATT do not specifically define what the Period of Investigation should be. From several case laws on safeguard measures, it is clear that neither the domestic laws on Safeguard nor Agreement on Safeguards and Article XIX of GATT provide specific guidelines on the period of investigation except the fact that the relevant investigation period should be sufficiently long to allow conclusion to be drawn on increased import and serious injury. The period of investigation in this case has been taken from 2011-12 to 2015-16 which is long enough to take into consideration the market conditions and to ascertain the need, if any, for imposition of Safeguard Duty.

(IV) Source of Information:

10. The import data till January, 2016 for the PUC has been taken from Export Import data bank, Ministry of Commerce (<http://www.commerce.nic.in/eidb/icomq.asp>) and the domestic data from 2011-12 to 2015-16 has been submitted by the applicant and the same has been verified by the department on the basis of excise records and other records maintained by the units to the extent deemed necessary.

(V) Confidentiality of Information submitted:-

11. The DI has provided some information on confidential basis and sought confidentiality on the information /data submitted. The DI provided non confidential version of the application for safeguard measures as per the provisions of Safeguard Duty Rules 1997 and Trade Notice No. SG/TN/1/97 dt. 06.09.1997. Further the DI has submitted reasons for seeking confidentiality at the time of filing the application.
12. Rule 7 of the Safeguards Duty Rules, 1997 and Art. 3.2 of WTO Agreement on Safeguards also provide for confidentiality. The applicant is not required to disclose such information which is confidential information of the company, disclosure of which can cause serious prejudice to the business interests of the company, which is not in public domain and which the applicant has not disclosed before public at large in the past. I have examined both the confidential as well as non-confidential version of the application and so far as the data and economic parameters being discussed here in the preliminary findings are concerned, the confidentiality, relating to those, as prayed for by the DI, is granted.

(VI) Unforeseen developments:

13. The Agreement on Safeguards read with Article XIX of GATT obligates the national authorities to examine the unforeseen developments which led to serious injury to the DI. Some of the unforeseen developments are detailed below:

(i) It is observed that China, which is a major producer accounting for almost half of the world Aluminium production, has witnessed a recent, sudden and unexpected drop in the growth rate of its economy leading to reduced consumption of Aluminium. This has resulted in huge surplus of Aluminium production capacities in China. The excess supply of Aluminium which was hitherto being consumed within China is now available for sale in the world market creating a glut and thus causing price depression in Aluminium to record low levels. In a number of cases, the Chinese Aluminium smelters are now being supported by the provincial Governments by way of powers subsidies, to keep those smelters running, as any closure of smelters would result in job cuts which the provincial Governments are unwilling to face. Therefore, despite being unviable due to weaker demand, the smelters continue to operate and feed the already over supplied world Aluminium market. Since China has export tax on Ingots and tax rebate on value added products, the exports from China is taking place on value added products of Aluminium. Some of the value added products also known as fake semis are exported with a view to avail the export rebate and avoid export tax. These fake semis are ultimately meant for re-melting into Ingots at the place of destination. All this was unforeseen by the Domestic Industry

(ii) On the other hand in the Middle East, a very significant increase in production capacity of Aluminium in the recent past, backed by very low energy cost, have resulted in surplus capacities at their end. With the already existing glut of Aluminium due to the excessive Chinese export to the world market, the Middle East producers have focussed their attention on the nearby freight friendly market of India.

14. It is observed that the above circumstances are unforeseen which has lead to significant increase in the imports of the PUC into India.

(VII) Increased Imports:

15. Imports of PUC into India are as detailed below:

Financial Year	Total Import (MT)	Import Indexed
2011-12	2,42,533	100
2012-13	3,08,279	127
2013-14	3,48,889	144
2014-15	3,43,428	142
2015-16 (April - Jan, 2016)	3,60,308	
2015-16 (Annualized)	4,32,370	178

It is seen that imports of the PUC have sharply increased during the injury period. The imports have increased from 2,42,533 MT in 2011-12 to 4,32,370 MT till 2015-16 (Annualized) recording an increase of 78 %. The most recent increase, between 2014-15 to 2015-16, has been quite sharp and significant.

(VIII) Serious Injury and Threat of Serious Injury:

16. **Serious Injury:** The applicants have claimed that the increased imports of PUC have caused and are threatening to cause serious injury to the domestic producers of PUC. They have in their petition, provided production, demand, inventory and other economic parameters of the industry justifying their claims. The data provided by the DI has been analysed as below:

a) **Production:** The domestic production of DI has increased during the period of investigation as shown below:

Financial Year	Production (MT)	Production Indexed
2011-12	8,87,286	100
2012-13	9,31,776	105
2013-14	10,51,100	118
2014-15	13,53,271	153
2015-16	15,63,639	176

b) **Increased Imports w.r.t total production:** PUC is imported into India from a number of countries, and mainly from UAE, Malaysia, Russia, South Africa, Oman, Qatar, Bahrain and Thailand. The imports of PUC have shown an increasing trend in absolute terms and as compared to the total production. The imports (Annualized) and production of PUC during financial year 2011-12 to 2015-16 are as under:

Financial Year	Total Imports (MT)	All India Production (MT)	% of import with respect to all India production
2011-12	2,42,533	19,27,464	13
2012-13	3,08,279	20,73,367	15
2013-14	3,48,889	20,88,900	17
2014-15	3,43,428	25,49,372	13
2015-16	4,32,370(Annualised)	28,18,978	15

The Imports have increased from 242533 MT in 2011-12 to 432370 MT in 2015-16 (Annualised) which shows an increase of 78%. It may be seen that import in the recent year 2015-16 has increased by 26% when compared to immediate preceding year 2014-15 which in my view is sudden, sharp and significant.

c) Market Share & Changes in levels of Sales: (MT in 000's)

Financial Year	Import	Sales of DI	Captive consumption	Sales of other Indian Producers	Total Demand	% of Market Share			Others
						Import	DI (excluding captive consumption)	DI (including captive consumption)	
2011-12	243	637	444	945	2,268	11	28	48	42
2012-13	308	718	568	997	2,592	12	28	50	38
2013-14	349	671	619	940	2,579	14	26	50	36
2014-15	343	670	605	1,135	2,754	12	24	46	41
2015-16	432 (Annualised)	894	538	1,064	2,928	15	31	49	36

During the period 2011-12 to 2015-16 the demand of the PUC has increased. The market share of import (Annualised) has increased from 11% in 2011-12 to 15% in 2015-16. During the same period the share of DI increased from 28% to 31%. However, when seen along with captive consumption, the share of DI has increased only by 1%.

d) Capacity Utilization: Even though there has been significant increase in demand of the PUC, the increasing imports have resulted in significant idling of production capacity of the domestic producers as can be seen in the Table below:

Financial Year	Installed Capacity (MT)	Production (MT)	Capacity Utilisation (%)	Total Demand
2011-12	23,25,096	8,87,286	38	22,68,453
2012-13	23,17,954	9,31,776	40	25,91,862
2013-14	25,57,393	10,51,100	41	25,78,900
2014-15	29,04,841	13,53,271	47	27,54,114
2015-16	32,58,465	15,63,639	48	29,27,819

e) Profit/loss –The profitability of the DI has steeply deteriorated in 2015-16 and the DI has recorded losses as can be seen from the table below:-

Financial Year	Domestic profit/loss (Rs/Kg) (Indexed)
2011-12	100
2012-13	11
2013-14	(4)
2014-15	154
2015-16 (Up to Dec,15)	(231)

f) Inventories –The table below depicts the inventory levels during the POI.

Financial Year	Inventory (in MT) Indexed
2011-12	100
2012-13	53
2013-14	46
2014-15	97
2015-16	49

g) Productivity & Employment: There is increase in the level of employment keeping in tandem with increasing capacity.

Financial Year	Production (MT)	Employment (Nos.)	Productivity per employee (MT)
2011-12	8,87,286	100	77
2012-13	9,31,776	95	85
2013-14	10,51,100	112	81
2014-15	13,53,271	111	105
2015-16	15,63,639	105	129

h) Price depression: It is noticed from the table below that during the last financial year 2015-16 there was price under selling due to the higher cost of sales vis-à-vis the landed price of imports which put the pressure on the domestic industry causing losses.

Particulars	Unit	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
Cost of sales (Indexed)	Rs/KG	100	109	110	117	118
Sales realisation	Rs/KG	100	104	104	119	99
Landed value (indexed)	Rs/KG	100	102	106	115	104
Profit/(loss) (Indexed)	Rs/KG	100	11	-4	154	-231
Price Under selling (Indexed)	Rs/KG	100	40	66	96	-32

17. There are a number of parameters on which the DI is showing positive trends, however, the most significant and the most dominant factor is profitability of the DI which has shown a serious downturn in the recent past due to increased imports arriving at depressed prices. In view of the above, it is seen that there is a deterioration in the financial parameters of the domestic industry causing losses to the DI due to which the domestic industry has suffered serious injury and immediate protection is required in the form of safeguard duty with a view to save the domestic industry from further injury.

18. Besides, threat of serious injury is also present in the current investigation. The imports of the PUC have increased significantly in absolute terms and in relation to production. As a result of significant surge in imports, the Domestic Industry has suffered serious injury and in all likelihood, the imports of the PUC will further increase and continue to threaten the domestic industry with serious injury.

(IX) Causal Link between Increased Import and Serious injury or Threat of Serious injury:

19. The Panel on Korea — Dairy (Para's. 7.89–7.90) set forth the basic approach for determining “causation”:

“In performing its causal link assessment, it is our view that the national authority needs to analyse and determine whether developments in the industry, considered by the national authority to demonstrate serious injury, have been caused by the increased imports. In its causation assessment, the national authority is obliged to evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry. In addition, if the national authority has identified factors other than increased imports which have caused injury to the Domestic Industry, it shall ensure that any injury caused by such factors is not considered to have been caused by the increased imports. To establish a causal link, Korea has to demonstrate that the injury to its Domestic Industry results from increased imports. In other words, Korea has to demonstrate that the imports of SMPP cause injury to the Domestic Industry producing milk powder and raw milk. In addition, having analyzed the situation of the Domestic Industry, the Korean authority has the obligation not to attribute to the increased imports any injury caused by other factors.”

20. A comprehensive evaluation of parameters enumerated above demonstrates that serious injury and threat of serious injury is being caused by increased imports. For the purpose of determining causation, all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of the industry have been evaluated. In the instant case, the following are relevant in this regard –

- i) The imports of PUC in absolute terms have increased significantly from 100% to 178% during the period of investigation.
- ii) The market share (including captive consumption) of domestic industry has remained stagnant leading to low capacity utilization despite increasing domestic demand.
- iii) The product is largely sold in comparison /competition with imports.
- iv) The landed price of import is significantly lower than the cost of sales in the recent period of 2015-16.
- v) Domestic industry is forced to export at a price lower than the domestic price in order to curtail the piling of inventories and to sustain production.
- vi) Profitability of domestic industry has deteriorated and they have incurred significant losses during 2015-16.

21. In view of the above I find that there is a direct correlation between the increase in imports and serious injury suffered by the domestic industry as imports increased by 78% during the year 2015-16(annualised) as compared to the base year 2011-12. This has affected the overall performance of the domestic industry which resulted in severe losses in the year 2015-16. It is therefore, evident that the injury suffered by DI is caused by increased imports.

(X) Developing Nations:

22. The percentages of imports from developing nations have also been examined for the year 2015-16. Except Malaysia, South Africa and Thailand other developing nations individually and collectively have less than 3% and 9% share respectively of total imports into India. Therefore, in terms of Notification No.19/2016-Cus dated 05.02.2016 imports of the product under consideration originating from developing nations except Malaysia, South Africa and Thailand will not attract Safeguard Duty in terms of proviso to Section 8B (1) of the Customs Tariff Act, 1975.

(XI) Critical Circumstances:

23. As per Rule 2(b) of Custom Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 the “Critical circumstances” means circumstances in which there is clear evidence that imports have taken place in such increased quantities and under such circumstances as to cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry and delay in imposition of provisional safeguard duty would cause irreparable damage to the domestic industry.

24. Rule 9 of Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 notified vide Notification No. 35/97-NT-Customs dated 29.07.1997 prescribes that the Director General shall proceed expeditiously with the conduct of the investigation and in critical circumstances, he/she may record a preliminary finding regarding “serious” or “threat of serious injury”. The principles governing investigations have been provided in the Rule 6 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty)

Rules, 1997. The harmonious reading of Rules 6 and 9 of the said Rules leads to a conclusion that the Rules provide for expeditious recommendation of provisional Safeguard duty based on preliminary findings. Rule 15 of the said Rules provide for refund of differential Safeguard duty in case safeguard duty imposed after conclusions of the investigations is lower than the provisional duty already imposed and collected.

25. The import of PUC into India has shown significant increase. Imports have increased by 78% in 2015-16 as compared to the base year of 2011-12 and 26% between 2014-15 and 2015-16. This increase in import at low prices have led to depression of price in the domestic market, forcing the DI to sell at prices below cost of sales, thus leading to unutilized and idling of huge capacities of the domestic industry during the period of investigation. Though domestic industry has huge installed capacity, it is unable to increase its production despite increase in domestic demand of the PUC.
26. Profitability of the domestic industry has sharply declined over the period to a situation where the domestic industry is now suffering severe financial losses and may not be able to sustain for a longer period of time without suffering irreparable damage to its future viability.
27. I observe that these are the factors which constitute critical circumstances in the instant case that have affected the overall performance of the domestic industry and have caused serious injury or threat of serious injury to the domestic industry. It is therefore considered appropriate to arrest the surge in imports in order to prevent further damage to the domestic industry.

(XII) Conclusion and recommendation:

28. On the basis of the preliminary findings above, I observe that increased imports of PUC have caused serious injury and threat of serious injury to domestic industry. As a result, the domestic industry has incurred financial losses in recent period 2015-16. The extent of financial losses may lead to a situation where it may make the DI, under the burden of financial liabilities, unviable in future. Thus, I find that critical circumstances exist where delay in imposition of safeguard measure would cause irreparable damage to the domestic industry, thus, necessitating immediate imposition of provisional Safeguard duty for a period of 200 days pending final determination of serious injury and threat of serious injury. Considering the average cost of sales of PUC by the domestic producers (confidential), a reasonable return on cost of sales excluding interest, the present level of import duties and present average import prices of PUC, provisional Safeguard Duty at the rate of 5% ad-valorem minus anti-dumping duty, if any, for 200 days which is considered to be the minimum required to protect the interest of domestic industry, is recommended to be imposed on imports of PUC.

(XIII) Further Process:

29. The information provided by various parties may be subjected to further verification where necessary, for which they will be informed separately
30. A public hearing will be held in due course before making a final determination, for which the date will be informed separately.

[F. No. D- 22011/10/2016/Pt-II]

VINAY CHHABRA, Director General.